(रु० लाख में)	25149
संयंत्र और मशीनरी में प्रति एकक निवेश (रु० लाख में)	0.34
अचल परिसम्पत्तियों मे निवेश (बही मूल्य) (रु० लाख में)	26015
अचल परिसम्पत्तियों में प्रति एकक निवेश (रु० लाख में)	0.35
रोजगार संख्या (कुल)	158808
प्रति एकक रोजगार (संख्या)	2
चालू मूल्यों पर प्रति एकक वर्धित मूल्य (रु० लाख में)	1.21

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान बंद लघु उद्योगों अथवा रुग्ण हो गये उद्योगों की संख्या का पता लगाने के लिए हाल में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की 1989-91 के दौरान जिसका संदर्भ वर्ष 1987-88 था, की गई दूसरी अखिल भारतीय गणना के निष्कर्षों से पता चलता है कि सर्वेक्षण के समय 44436 एकक बंद थे/इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये एकक 15 वर्ष की अवधि के दौरान बंद हुए थे अर्थात् लघु औद्योगिक एककों की पहली गणना के पश्चात जिसका संदर्भ वर्ष 1972 था। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताया गया है 31.3.1992 को स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 22333 रुग्ण लघु एकक थे।

(ङ) जीव्यक्षम रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए राज्य स्तरीय अन्तर्संस्थागत समितियों और राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना समितियों के जरिये नियमित आधार पर उपाय किये जा रहे हैं। बैंक भी नियमित आधार पर जीव्यक्षम रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना मे मदद करते है। राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों, जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। लघु औद्योगिक एककों की रुग्णता संबंध समस्याओं से शीघ्रता से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि रुग्ण औद्योगिक एककों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रकोष्ठ स्थापित करें और तकनीकी कार्मिकों सहित विशेषज्ञों की व्यवस्था करायें।

Schemes for development of Khadi in Gujarat

4138. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of schemes formulated for the development of Khadi and Village Industries in Gujarat alongwith details of grants provided by Government to various Khadi and Village Industries centres in the State during the year 1991-92 and 1992-93;

(b) whether Government had enhanced the grant during the year 1993-94;

(c) if so, what are the details in this regard; and

(d) what steps have been taken or are proposed to be taken to make Khadi popular in the State and other parts of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) In addition to Khadi (Cotton, Woollen & Silk) Programme, number of village industries including new schemes such as cottage pottery, agarbatti, handmade paper, cane & bamboo, ghani oil, gur & khandsari, processing of cereals & pulses, cottage soap and cottage leather, bio-gas, carpentary & blacksmithy, polyvastra etc. arc implemented by Gujarat State KVI Board as well as departmental units of KVIC in rural areas of Gujarat.

The details of funds provided for various KVI Programme in Gujarat during the years 1991-92, 1992-93 & 1993-94 are as under:—

(Rs. in lakhs)

Year	Funds Released	
	Grant	Loan
1991-92	431.71	118.45
1993-94	833.95	217.33
1993-94	779.09	241.36

(d) The following steps have been taken to popularise khadi in the country including Gujarat:—

(i) Improvement in quality of raw-material through setting up of central sliver plants.

(ii) Improvement in quality of the yarn through introduction of high speed new model charkhas and S spindle charkhas for cotton & polyvastra; medlery & Bhageswari (2 spindle) charkhas for woollen etc.

(iii) Improvement in quality of fabric through improvement looms, processing etc.

(iv) Enabling institutions to set up khadi bhandars etc. by arranging finance from commercial banks, SIDBI etc.

(v) Continuing the rebate system as an incentive to buy khadi.

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

4139. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1980 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं; और

(ग) ये उद्योग किन-किन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और इनमें किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होता है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) औद्योगिक नीति 1980 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

अधिक रोजगार का सृजन करना,
औद्योगिक क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर विकास करना,
पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना,
कृषि आधार को मजबूत करने के लिए कृषि उद्योग को प्राथमिकता देना,
उपभोक्ता संरक्षण,
आर्थिक संघवाद को बढ़ावा देना,
अधिकतम उत्पादन करना और
अधिक उत्पादकता प्राप्त करना,
अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करना।

(ख) और (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अनुसार कानपुर देहात, अल्मोड़ा, फैजाबाद, देवरिया, मथुरा, गोंडा, मुरादाबाद, आगरा, गाजियाबाद, ललितपुर, खीरी नैनीताल, बरेली, बिजनौर इत्यादि जैसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1991 से 1993 के दौरान कुल 53 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये थे। ये लाइसेंस धातुकर्मी उद्योग, ईंधन, वैद्युत उपकरण, दूरसंचार परिवहन, रसायन औषध और फेंसेज, कपड़ा, चीनी फर्मेन्टेशन उद्योग चमड़ा इत्यादि जैसे अनुसूचित उद्योगों से संबंधित विभिन्न मदों का निर्माण करने के लिए दिये गये थे।

क्योंकि एक औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में सामान्यतः 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं अतः उपर्युक्त औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

Allocation of Funds for Development of Rural Industries

4140. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA:
SHRI AAS MOHAMMAD:

Will the PRIME MINISTER be pleased, to state:

(a) whether the Union Government have reduced the allocation for the development of rural industries during 1993-94 as compared to the last year as a result of which there has been an adverse impact on the development of rural industry;

(b) if so, the details thereof;

(c) the amount allocated separately during the last three years for the development of rural industries; and

(d) the reasons for reducing this amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M.